जीएम सरसों की मंजूरी का कृषि वैज्ञानिकों ने किया स्वागत

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 27 अक्टूबर

जीन संवर्धित (जीएम) सरसों को परीक्षण मंजूरी मिलने से वैज्ञानिक समुदाय उत्साहित है। उनका मानना है कि इससे कुछ नई अच्छी खबरें आएंगी, लेकिन कुछ वैज्ञानिक 2010 के बीटी बैगन को लेकर उपजे विवाद जैसी स्थिति पैदा होने को लेकर आशंकित हैं। उस समय विवादों के बाद अंतिम क्षण में मंजूरी रोक दी गई थी।

बहरहाल सूत्रों का कहना है कि 2010 और 2017 की स्थिति आने की संभावना नहीं है, जब जीएम फसलों को जीईएसी की मंजूरी आखिरकार नहीं मिल पाई थी। सूत्रों के मुताबिक जीईएसी की बैठक का ब्योरा पर्याप्त है, जिससे संकेत मिलते हैं कि सभी मंजूरियां हासिल कर ली गई हैं।

जीईएसी ने प्रोफेसर दीपक पेंटल को भी पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि उनके आवेदन के आधार पर समिति ने भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के दिशानिर्देशों के अनुसार धारा मस्टर्ड हाइब्रिड (डीएमएच)-11 के बीज उत्पादन और परीक्षण को मंजूरी दे दी है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह साफ संकेत है कि कोई भी विसंगति नहीं छोड़ी गई है। उधर आईसीएआर ने बीती रात कई ट्वीट करके इस कदम का स्वागत किया और कहा कि इस मंजूरी से ज्यादा उपज वाले हाइब्रिड सरसों के लिए राह खुल गई है, जो भारत में लोकप्रिय सरसों की किस्मों का जीन संवर्धित मिश्रण है।

आईसीएआर कृषि मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन है। यह जीएम सरसों के अध्ययन में शामिल रहा है। आईसीएआर ने कहा है कि जीएम सरसों हाइब्रिड डीएमएच-11 में सरसों की उत्पादकता सुधारने की क्षमता है। सरसों का उत्पादन 1 टन प्रति हेक्टेयर है, जबकि वैश्विक उत्पादन मानक करीब 3 टन प्रति हेक्टेयर है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत काम करने

कुछ वैज्ञानिक 2010 के बीटी बैगन को लेकर उपजे विवाद जैसी स्थिति पैदा होने को लेकर आशंकित हैं

वाले नैशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने भी मंजूरी का स्वागत किया है और कहा है कि जीईएसी का यह फैसला मील का पत्थर है और इससे जीएम तकनीक को बढ़ावा मिलेगा, जिसका लाभ किसानों को मिलेगा।जाने माने वैज्ञानिकों डॉ आरएस परोदा, आईसीएआर के पूर्व महानिदेशक के विजयराघवन और भारतीय कृषि शोध संस्थान (आईएआरआई) के मौजूदा निदेशक डॉ. एके सिंह ने मंजूरी का स्वागत करते हुए इसे मील का पत्थर करार दिया है।

शुक्रवार को नैशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज (एनएएएस), आईसीएआर और ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट आफ एग्रीकल्चरल साइंस (टीएएसएस) के वरिष्ठ वैज्ञानिक संवाददाता सम्मेलन करेंगे और इस मंजूरी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।

नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और जाने माने अर्थशास्त्री अरविंद पानगडिया ने ट्विटर पोस्ट में लिखा है, 'जीएमओ सीड्स को सरकार की ओर से मंजूरी मिलने से खुश हूं। मैंने नीति आयोग में रहते इसके लिए लड़ाई लड़ी और मंजूरी के करीब पहुंचे, लेकिन आखिरकार ऐसा नहीं हो सका। उम्मीद करता हूं कि इस बार स्थिति इससे अलग होगी।'